CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 28 □ अंक- 263 □ रायपुर, शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

208 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष किया आत्मसमर्पण

110 महिला नक्सली शामिल, पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ : साय

–**जगदलपुर,** 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। जगदलपुर आज नक्सलियों ने सबसे बड़ी संख्या में हथियार डालकर सरेंडर किया है. बस्तर संभाग के अबूझमाड़ और कांकेर के जंगलों से निकलकर कुल 208 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है. इनमें 110 महिला नक्सली है और 98 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो सीसी मेंबर के साथ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जन जनमिलिसिया कमेटी के अलावा 7 अन्य कैडर पर पदस्थ रहे हैं. सभी ने जगदलपुर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री साय के समझ हथियार डाले हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी समते पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलियों ने 9 प्रकार के 153 हथियार डालकर सरेंडर किया. इनमें 19 एके 47, 17 एसएलआर राइफल, 23 इंसास राइफल, एक इंसास एलएमजी, 36 नग 303 राइफल, 4 कार्बाइन, 11 बीजीएल लॉन्चर, 41 नग 12 बोर/ सिंगल शॉट और 1 पिस्टल शामिल हैं. देश के सबसे बड़े नक्सली को लेकर रायपुर से रवाना होने के दौरान सीएम साय ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत है. उन्हें हमारी (राज्य सरकार) अच्छी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा. हमने शुरू से ही हथियार छोड़ने का नक्सलियों से आह्वान किया था.

नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर

एके 47, एसएलआर और इंसास समेत डाले 153 हथियार

खाली हो जाएगा माड़ डिविजन

भैरगगढ़ से सरेंडर के लिए रवाना होने वाले नक्सलियों में नक्सली प्रवक्ता रूपेश के अलावा 1 सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसीएम), 2 दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (डीकेएसजेडसी), 15 डिविजनल कमेटी मेंबर (डीवीसीएम), एक माड़ एसीएम और 121 अन्य कैडर के माओवादी शामिल हैं. इसी के साथ अधिकतम अबूझमाड़ नक्सल मुक्त होगा और उत्तर बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद का सूपड़ा साफ होना रह गया है. इन 7 कैडरों के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें सीसीएम-1 कैडर, डीकेएसजेडसी 4 कैडर, रीजनल कमेटी मेंबर 1 कैडर डीवीसीएम 21 कैडर, एसीएम लेवल 61 कैडर, पार्टी मेंबर 98 कैडर और पीएलजीए मेंबर/ आरपीसी मेंबर/ अन्य 22 शामिल हैं।

कर्मचारियों को तोहफा, दीपावली से पूर्व वेतन का अग्रिम भुगतान

रायपुर, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. वित्त विभाग ने आदेश जारी कर अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से 17 और 18 अक्टूबर को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर अग्रिम वेतन का फैसला- राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 206(1) के तहत यह विशेष निर्णय लिया है. सामान्यत- कर्मचारियों को माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में वेतन मिलता है, लेकिन इस बार दीपावली पर्व की खुशियों को देखते हुए सरकार ने इसे पहले देने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2025 का वेतन 17 और 18 अक्टूबर को कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाएगा. राज्य के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर 18 अक्टूबर (शनिवार) तक कोषालय में प्रस्तुत करेंगे. इस दिन सभी कोषालय खुले रहेंगे ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मजदूरी, मानदेय और पारिश्रमिक जैसे मदों में भी जरूरत के अनुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा. इससे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी समय से त्योहार मनाने में सहूलियत होगी। निगम-मंडल और आयोगों को भी निर्देश- राज्य शासन ने अपने अधीनस्थ सभी निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग और विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय स्थिति देखते हुए अग्रिम भुगतान पर विचार करने की अनुमति दी है. इससे राज्य के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी त्योहारी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. वेतन के अग्रिम भुगतान से बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी रफ्तार मिलेगी. कर्मचारियों ने इस फैसले को सरकार का सच्चा दिवाली बोनस बताया है।

ब्रेकिंग न्यूज

नामांकन के आखिरी दिन शाह-नीतीश की अहम मुलाकात

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन हुई। शाह ने गुरुवार को पुष्टि की थी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेगा। एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए, पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि वह जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे।

शाह ने एनडीए के सहयोगी दलों पर उम्मीद जताते हुए कहा था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं,

अब जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म

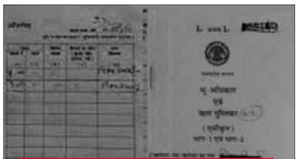

साय सरकार का ऐतिहासिक फैसला

रायपुर, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)।जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई की होगी, या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है. इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी. अब साय सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है.

पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रदेश के तमाम जिला पंजीयकों को ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें पंजीयकों से अधीनस्थों को जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यकता समाप्त किए जाने के संबंध में निर्देशित करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है.

छुही मिट्टी खदान धंसने से एक महिला की मौत, एक घायल, बाल-बाल बचे दो लोग

बलरामपुर, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। छुहीमिट्टी खदान धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गई. दो महिलाएं बाल-बाल बचीं. महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मृत व घायल व महिला को बाहर निकाला।

घटना वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के मदनपुर की है. दिवाली के अवसर पर घर की पुताई के लिए ग्रामीण महिलाएं छुहीमिट्टी खदान से मिट्टी निकाल रही थीं. इस दौरान ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे एक महिला की नीचे दबने से मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गई. महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, गुजरात में मुख्यमंत्री छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई।

चुहिया- हां जी, गुजरात सरकार का सर्विसिंग की गई है..!

गन्ना उत्पादकों को मिला 5.98 करोड़ का तोहफा

दीपावली से पहले किसानों के चेहरे खिले

कवर्धा/पंडरिया, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। दीपावली पर्व से पहले कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य शासन ने वर्ष 2024-25 के पेराई सत्र के लिए गन्ना विक्रेता किसानों को प्रति क्विंटल 39.90 रुपए की दर से 5 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है.

यह राशि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. पंडरिया को प्राप्त हुई है. शासन से राशि मिलने के बाद कारखाना प्रबंधन द्वारा कुल 7,658 गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में यह धनराशि सीधे बैंक के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. यह निर्णय दीपावली से ठीक पहले आने के कारण किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. किसान अब त्योहार को और अधिक हर्षोल्लास से मना सकेंगे. किसानों ने इस निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और विधायक भावना बोहरा के प्रति आभार व्यक्त किया है. कारखाना प्रबंधन ने बताया कि गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का उद्देश्य उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कहा कि किसानों के हित और खुशहाली ही उनकी प्राथमिकता है, और यह प्रयास उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है. त्योहार के इस मौसम में राज्य शासन की यह पहल निश्चित रूप से किसानों के लिए दीपावली का बोनस तोहफा साबित हो रही है,

मोदी-शाह के भरोसेमंद हर्ष सांघवी अब गुजरात के उपमुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। गुजरात भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार, शपथ लेने वालों में स्वरूपजी ठाकोर, प्रवीणकुमार माली, रुशिकेश पटेल, दर्शना वाघेला, कुंवरजी बावलिया, रीवाबा जडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, जितेंद्र वाघानी, प्रफुल पनशेरिया और कनुभाई देसाई शामिल थे। हर्ष सांघवी की शपथ से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य के सभी 16 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए इस्तीफा दे दिया था। 40 वर्षीय हर्ष संघवी राज्य की राजनीति में अपनी तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और अक्सर उन्हें युवाओं का आदर्श माना जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी सहयोगी माना जाता है।

'सेवा-पानी' के नाम पर डीआईजी के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद

1.5 किलो सोना-हीरे लग्जरी कारें जब्त कैश इतना मंगानी पड़ी 3 मशीनें

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (न्यूज चैनल)। पंजाब के पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (छ्इूत्र) हर्चरण सिंह भुल्लर को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इससे शुरू हुई जांच में उनके खिलाफ ऐसे राज़ सामने आए हैं, जिनसे भ्रष्टाचार की गहराई और बड़े पैमाने का अहसास होता है।

सीबीआई की छापेमारी के दौरान भुल्लर के घर और कार्यालय से करोड़ों की नगदी, 1.5 किलो सोना, लग्जरी घड़ियां, महंगी कारों की चाबियां, विदेशी शराब और हथियार बरामद हुए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भुल्लर ने पंजाब के कई शहरों और हिमाचल के सोलन में भी बड़ी संपत्तियों में निवेश किया है, जो उनकी काले धन की संपत्ति का प्रमाण है।

मंडी गोबिंदगढ़ के बिजनेसमैन आकाश बत्ता ने 11 अक्टूबर को सीबीआई को शिकायत दी कि डीआईजी भुल्लर ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुरानी एफआईआर (थाना सिरहिंद, नंबर 155/2023) को दबाने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की है। इसके साथ ही मासिक तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई, जिसे 'सेवा-पानी' कहा गया। जब व्यापारी ने पैसे देने से मना किया तो भुल्लर ने धमकाया कि झूठे केस में फंसा देंगे और उसका कारोबार चौपट कर देंगे। बिजनेसमैन ने सीबीआई से संपर्क कर मदद मांगी, जिसके बाद एजेंसी ने एक जाल बिछाया। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को हुई एक व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड की, जिसमें डीआईजी अपने दलाल कृष्णु को स्पष्ट रूप से 8 लाख रुपये की वसूली के निर्देश देते हुए सुने गए।

नवगठित सक्ती जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना में रचा नया कीर्तिमान

30 हजार से अधिक परिवारों को मिला पक्का घर

प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंचा सक्ती जिला

रायपुर, 17 अक्टूबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के नवगठित सक्ती जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में एक नया इतिहास रच दिया है. नवगठित जिला होने के बावजूद, सक्ती ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 2024-25 में 30 हजार 512 आवास पूर्ण कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि न केवल संख्यात्मक सफलता का प्रतीक है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन में आई स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान की कहानी भी है, जिन्होंने वर्षों तक कच्चे और असुरक्षित मकानों में जीवन व्यतीत किया था.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सक्ती जिले में अब तक वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 44 हजार 319 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया, जो 95: लक्ष्य प्राप्ति दर्शाता है. वहीं, वर्ष 2024-25 में 30 हजार से अधिक मकान पूर्ण कर जिले ने मिशन मोड में कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है. हर ग़रीब का पक्का घर राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता रही है . मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में

यह योजना प्रभावी ढंग से संचालित हुई. नियमित फील्ड विजिट, समयबद्ध वित्तीय सहायता, और हितग्राहियों के साथ सतत संवाद के परिणामस्वरूप यह उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई.

CMYK